नीति आयोग और महत्वपूर्ण रिपोर्ट

नीति आयोग को अखिल भारतीय स्तर पर वित्तीय योजना के लिए बनाया गया है और यह विभिन्न मापदंडों का आकलन करने वाले विकास के लिए महत्वपूर्ण रिपोर्टें जारी करता है। इसके बारे में विस्तार से जानने से पहले आइए संक्षेप में भारत में योजना निकाय के पहले के संस्करण का पता लगाएं। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा की गई थी। इसे राष्ट्रीय संसाधनों का आकलन करने और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए पंच वर्षीय योजनाओं का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसका उद्देश्य संसाधनों का समुचित और प्रभावी उपयोग करना था। बदलते समय और लोगों की बढ़ती जरूरतों और उनका प्रभावी ढंग से समाधान करने के साथ ही योजना आयोग के स्थान पर 01 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा योजना निकाय अर्थात नीति आयोग का एक नया संस्करण स्थापित किया गया।

नीति आयोग को भारत सरकार की प्रमुख नीति 'थिंक टैंक' माना जाता है। यह दिशात्मक और नीतिगत दोनों तरह की जानकारियां प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करने के अलावा, आयोग केंद्र के साथ-साथ राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है।

नीति आयोग का संरचनात्मक संयोजन

नीति आयोग के मूल में दो हब हैं: 'टीम इंडिया हब' और 'नॉलेज एंड इनोवेशन हब'। ये हब आयोग के दो प्रमुख कार्यों को दर्शाते हैं।

- टीम इंडिया हब केंद्र सरकार के साथ राज्यों की सम्बद्धता का नेतृत्व करता है।
- नॉलेज एंड इनोवेशन हब नीति की थिंक टैंक क्षमताओं का निर्माण करता है।

जरूरी संसाधनों, ज्ञान और कौशल के साथ नीति आयोग खुद को अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में भी विकसित कर रहा है। यह अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, रणनीतिक नीति प्रदान करने और सरकार के लिए विजन को तेज गति प्रदान करने और आकस्मिक मुद्दों से निपटने में सक्षम होगा।

नीति आयोग के सदस्य :

1. अध्यक्ष: श्री नरेंद्र मोदी
2. उपाध्यक्ष : डॉ राजीव कुमार
3. पूर्णकालिक सदस्य : प्रो रमेश चंद
4. पूर्णकालिक सदस्य : प्रोफाइल - श्री वीके सारस्वत
5. पूर्णकालिक सदस्य : प्रोफाइल – डॉ. वी.के. पॉल
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी : श्री अमिताभ कांत

byjusexamprep.com

नीति आयोग का उद्देश्य

नीति आयोग का उद्देश्य भारत की राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी और प्रतिभागिता को बढ़ावा देना है। यह सहकारी संघवाद को अपनाने की परिकल्पना करता है। नीति आयोग की राज्यों, केंद्र और जिलों सहित पूरे भारत के कायांतरण की इच्छा है। यह स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, शासन तंत्र को मजबूत करने जैसे क्षेत्रों में विकास की परिकल्पना करता है और उन्हें आकांक्षी जिलों में लागू करता है और प्रगति की निगरानी करता है। इस संबंध में नीति आयोग विभिन्न मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए रिपोर्ट जारी करता है। आइए नीति आयोग द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टों पर चर्चा करते हैं।

1. **भारत नवाचार सूचकांक (III)**

भारतीय राज्यों में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग 'भारत नवाचार सूचकांक' पेश किया है। यह पहला ऐसा सूचकांक है जिसका उद्देश्य देश भर में नवाचार के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को सुगम बनाना है।

नवाचार क्यों आवश्यक है?

नवाचार हमेशा किसी भी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और प्रगति का चालक रहा है क्योंकि यह पारंपरिक प्रथाओं और व्यवसायों को बाधित करता है। यह सूचकांक राज्यों को नवाचार जलवायु को बढ़ावा देने के लिए अपनी रणनीति तैयार करने में मदद करेगा, यह अन्य राज्यों के साथ अपने प्रदर्शन के मानदण्ड तय करने में सक्षम बनाएगा। इसलिए, भारत नवाचार सूचकांक को अपने दो आयामों – समर्थन और प्रदर्शन के स्कोर का औसत माना जाता है।

सूचकांक को दो मुख्य शीर्षकों के तहत समूहित किया गया है :

- समर्थक : ऐसे कारक जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नवाचार को चलाएंगे
- प्रदर्शन : राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिणामों को मापने में सक्षम

उद्देश्य : दोहरे उद्देश्यों में राज्य की नवाचार रैंकिंग और राज्यों को बेहतर बनाने के लिए सशक्त बनाना शामिल है। समर्थक वे कारक हैं जो अभिनव क्षमताओं को रेखांकित करते हैं, पांच समर्थक स्तंभ (जो अभिनव क्षमताओं को सक्षम बनाता है) निम्नलिखित हैं :

1. मानव पूंजी
2. निवेश
3. ज्ञान कार्यकर्ता
4. कारोबारी माहौल
5. सुरक्षा और कानूनी वातावरण

byjusexamprep.com

प्रदर्शन आयाम उन लाभों को प्राप्त करता है जो कि एक राष्ट्र को आदानों से प्राप्त होते हैं और दो प्रदर्शन स्तंभ हैं :

1. ज्ञान का प्रकटीकरण
2. ज्ञान प्रसार

भारत इनोवेशन इंडेक्स 2021 में राज्य का रैंक:

Rank	Major States	Score
1	KARNATAKA	42.50
2	MAHARASHTRA	38.03
3	TAMIL NADU	37.91
4	TELANGANA	33.23
5	KERALA	30.58
6	HARYANA	25.81
7	ANDHRA PRADESH	24.19
8	GUJARAT	23.63
9	UTTAR PRADESH	22.85
10	PUNJAB	22.54
11	WEST BENGAL	21.69
12	RAJASTHAN	20.83
13	MADHYA PRADESH	20.82
14	ODISHA	18.94
15	JHARKHAND	17.12
16	CHHATTISGARH	15.77
17	BIHAR	14.48

Rank	NE and Hill States	Score
1	HIMACHAL PRADESH	25.06
2	UTTARAKHAND	23.50
3	MANIPUR	22.78
4	SIKKIM	20.28
5	MIZORAM	16.93
6	ASSAM	16.38
7	ARUNACHAL PRADESH	14.90
8	NAGALAND	14.11
9	TRIPURA	12.84
10	MEGHALAYA	12.15

Rank	UT and City States	Score
1	DELHI	46.60
2	CHANDIGARH	38.57
3	DAMAN & DIU	26.76
4	PUDUCHERRY	25.23
5	GOA	24.92
6	DADRA & NAGAR HAVELI	22.74
7	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	18.89
8	JAMMU & KASHMIR	18.62
9	LAKSHADWEEP	11.71

1. **एसडीजी इंडिया इंडेक्स**

देश और उसके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति के समग्र दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स तैयार किया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास एजेंडा 2030 के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई और देश के अधिकांश राष्ट्रीय विकास एजेंडा सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में नजर आते हैं। नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स - बेसलाइन रिपोर्ट 2018 को सामने लाकर बढ़त हासिल की है और यह दिखाया है कि एसडीजी को भारत में कैसे मापा जाएगा। सूचकांक एक समग्र उपाय है जो नीति निर्माताओं, व्यवसायों, नागरिक समाज और आम जनता हो सकता है।

- यह भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 2030 एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में की गई प्रगति का व्यापक रूप से दस्तावेजीकरण करता है।
- इसे भारत में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), संयुक्त राष्ट्र और ग्लोबल ग्रीन इंस्टीट्यूट के सहयोग से विकसित किया गया है।
- यह एमओएसपीआई के नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क (एनआईएफ) से तैयार किए गए 100 संकेतकों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति की निगरानी करता है।
- सूचकांक लक्ष्य 17 पर गुणात्मक आकलन के साथ 17 एसडीजी में से 16 तक विस्तारित है।
- यह 2018 सूचकांक पर सुधार का प्रतीक है जिसमें केवल 13 लक्ष्य शामिल हैं।
- प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए 0-100 की सीमा में एक समग्र स्कोर की गणना 16 एसडीजी में इसके कुल प्रदर्शन के आधार पर की जाती है, जो 16 एसडीजी और उनके संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रत्येक राज्य/यूटी के औसत प्रदर्शन को दर्शाता है।
- यदि कोई राज्य/यूटी 100 का स्कोर प्राप्त करता है, तो यह दर्शाता है कि उसने 2030 के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का स्कोर जितना अधिक होगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उतना ही अधिक होगा।
- एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्कोर के आधार पर वर्गीकरण मानदंड इस प्रकार है :

1. आकांक्षी : 0-49
2. प्रदर्शक : 50-64
3. अग्रणी : 65-99
4. सफल : 100

byjusexamprep.com

एसडीजी इंडेक्स में राज्यों की रैंक:

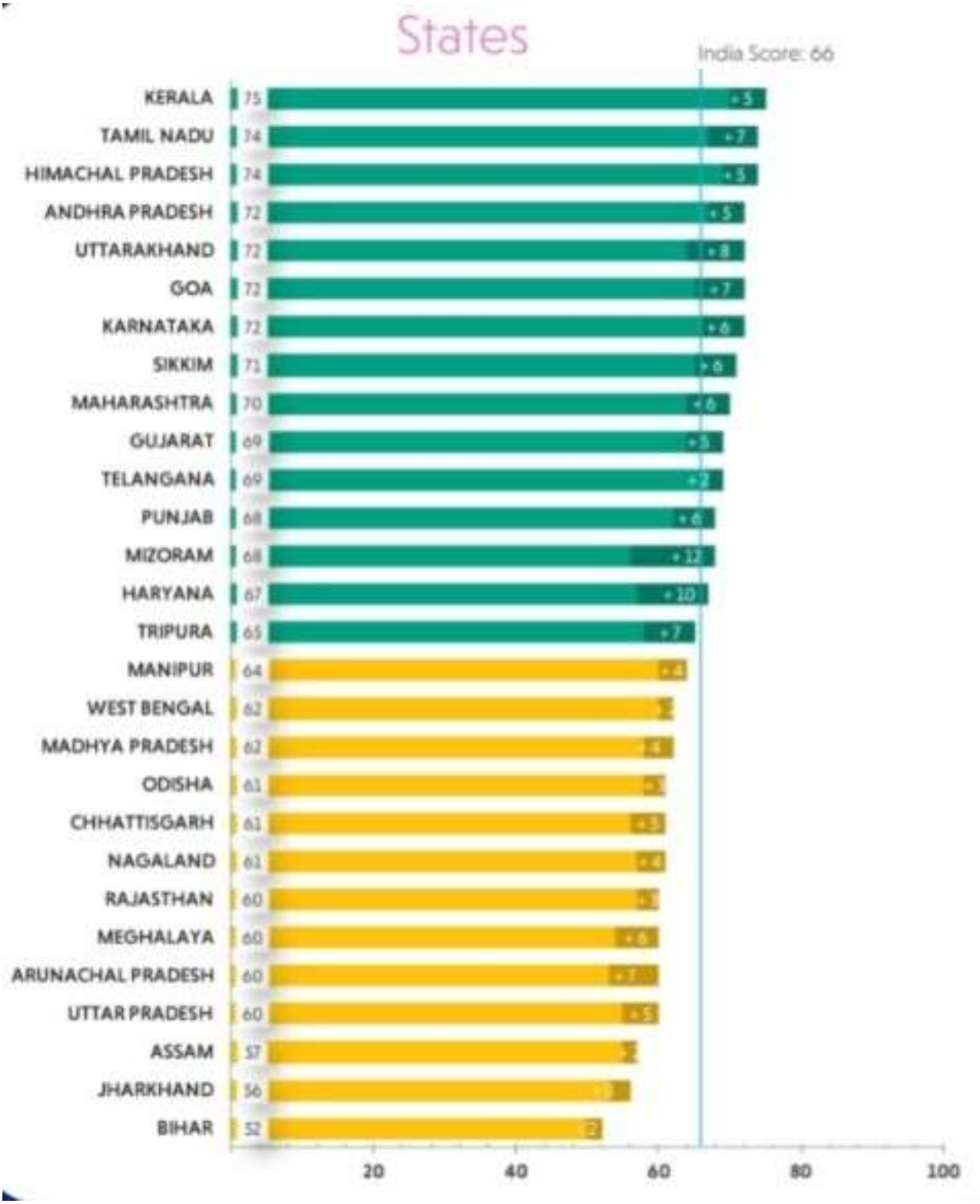

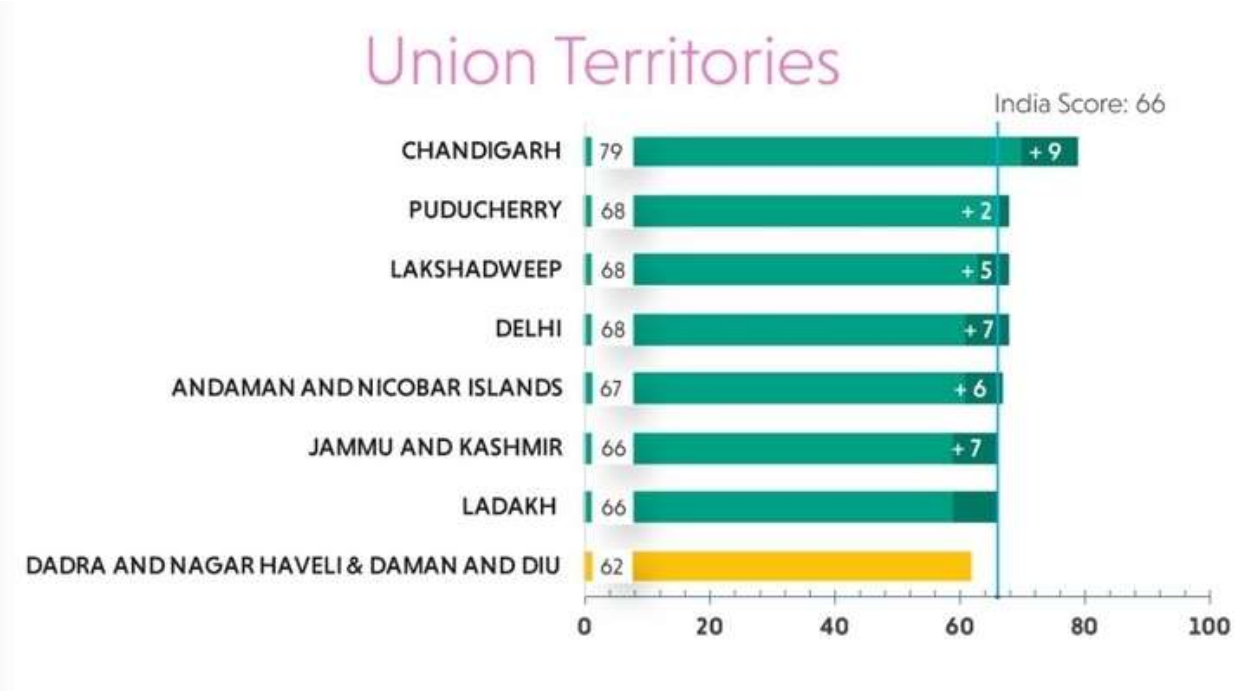

स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (SEQI)

स्कूल शिक्षा क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (एसईक्यूआई) विकसित किया गया था।

उद्देश्य

एसईक्यूआई का उद्देश्य नीतिगत सुधारों को परिचालित करना है जिससे स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। समान तुलना को सुगम बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समूहों को बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में समूह बनाया गया है।

- सूचकांक में सीखने के स्तर, पहुंच, इक्विटी, बुनियादी ढांचे और प्रशासन प्रक्रियाओं में सुधार चलाकर शिक्षा परिणामों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया है।
- इन समूहों में से प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक समग्र प्रदर्शन स्कोर और रैंकिंग उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक के भीतर, संकेतक मूल्यों को उचित रूप से मापा गया है, सामान्यीकृत किया गया है और मान दिया गया है।

श्रेणी	क्षेत्र	संकेतकों की संख्या	कुल मान
1. परिणाम	1.1 सीखने के परिणाम	3	360
	1.2 पहुंच परिणाम	3	100
	1.3 परिणामों के लिए बुनियादी ढांचा और	3	25

	सुविधाएं		
	1.4 निष्पक्षता परिणाम	7	200
2. परिणामों में सहायक शासन प्रक्रियाएं	छात्र और शिक्षक उपस्थिति, शिक्षक उपलब्धता, प्रशासनिक पर्याप्तता, प्रशिक्षण, जवाबदेही और पारदर्शिता शामिल	14	280
कुल		**30**	**965**

2020 में, दुनिया एसडीजी को प्राप्त करने के लिए अंतिम दशक-**'कार्रवाई दशक'** में प्रवेश करती है**। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2.0** और डैशबोर्ड भारत को अपने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसडीजी को पूरा करने के लिए त्वरित प्रगति की निगरानी करने और प्रोत्साहित करने के लिए सक्षम बनाना चाहते हैं।

समग्र जल प्रबंधन सूचकांक

- समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट देश में जल संकट की वास्तविकताओं के बारे में लोगों और सरकारों के बीच जागरूकता पैदा करने की दिशा में एक कदम है।
- CWMI का उद्देश्य इस बढ़ती संकट की स्थिति में भारतीय राज्यों में प्रभावी जल प्रबंधन को सक्षम बनाना है।
- नीति आयोग ने समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में सभी राज्यों को 28 विभिन्न संकेतकों के साथ स्थान दिया है, जिसमें भूजल के विभिन्न पहलुओं, जल निकायों की बहाली, सिंचाई, कृषि पद्धतियों, पेयजल, नीति और शासन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करता है।

सीडब्ल्यूआई विषय और मान

क्र. सं.	**क्षेत्र**	**मान**
1	जल निकायों का स्रोत संवर्धन और बहाली	5
2.	स्रोत वृद्धि (भूजल)	15
3.	प्रमुख और मध्यम सिंचाई- आपूर्ति पक्ष प्रबंधन	15
4.	जलभंडार विकास - आपूर्ति पक्ष प्रबंधन	10
5.	भागीदारी सिंचाई विधियां - मांग पक्ष प्रबंधन	10

byjusexamprep.com

6.	टिकाऊ ऑन-फार्म जल उपयोग विधियां- मांग पक्ष प्रबंधन	10
7.	ग्रामीण पेयजल	10
8.	शहरी जलापूर्ति और स्वच्छता	10
9.	नीति और प्रशासन	15
कुल		**100**

- नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार, भारत में 75% घरों में अपने परिसर में पीने के पानी की सुविधा नहीं है, और भारत जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में 120वें स्थान पर है।

byjusexamprep.com